बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजनायें

3516. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या देश में लगभग 10 लाख बीड़ी श्रमिक हैं ;

(ख) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में उन बीड़ी श्रमिकों के लिए, जिनके पास भूमि और मकान नहीं है आवास योजनाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लगभग 6 लाख व्यक्ति बीड़ी के पत्तों को एकत्र करने के काम पर (6 से 8 सप्ताह तक के लिए) लगे हुए हैं और अन्य 18 लाख व्यक्ति बीड़ी बनाने के काम पर लगे हुए हैं। ये आंकड़े कारखाना क्षेत्रक से सम्बन्धित हैं। उनके अलावा कारखाने से इतर क्षेत्रक में काफी रोजगार है (लगभग 17 लाख श्रमिक)।

(ख) और (ग). 1980-85 की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग में तैयार किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्रक में मौजूदा सामाजिक आवास स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और वे व्यापार और व्यवसाय पर आधारित न होकर मानदंड के रूप में आय पर आधारित है। औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत आर्थिक सहायता प्राप्त आवास स्कीम 500 रु० प्रति मास से कम आय वाले सभी औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लागू है, जिसमें यह परंतुक है कि 350 रु० तक की मासिक आय वाले लोगों की धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जानी चाहिए। इस स्कीम में पूंजी और किराया--इन दोनों की ही आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की आवास स्कीमों में, ब्याज की रियायती दरों पर, उन लोगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने की परिकल्पना है जिनकी मासिक आय क्रमशः 351 रु० से 600 रु० तक और 601 रु० से 1500 रु० तक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ग्रामीण आवास स्थल और आवास निर्माण स्कीम को परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है उस में जिन ग्रामीण श्रमिकों के पास अपना प्लाट या मकान नहीं है, उनको मुफ्त में आवास स्थल और निर्माण के लिए प्रति परिवार 500 रु० की सहायता की परिकल्पना है। इसके अलावा, ग्राम आवास परियोजना स्कीम में गांवों में मकानों के निर्माण और सुधार के लिए राज्य सरकारों से ऋण सहायता की व्यवस्था है। यह ऋण की राशि निर्माण की लागत के 80 प्रतिशत तक सीमित है जो प्रति आवास अधिकतम 5,000 रु० हो सकती है।

Survey of Backward Distt. for Industrial Development particularly in Orissa

3517. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have under its consideration any fresh move for conducting survey of the potentialities of the industrial development in the backward districts of the country, particularly in the State of Orissa; and

(b) if so, what are the States where such survey are being conducted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). The Government of India has not been conducting district techno-economic surveys. The financial institutions like the Industrial Development Bank of India have conducted surveys of selected districts out of the districts identified as industrially backward.

Recruitment in Army

3518. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the candidates desirous to be recruited in the Army are asked to go for recruitment in the area to which they belong;

(b) is it also a fact that in the past the candidate could be recruited in any Recruiting Office;

(c) is it also a fact that there is a very old Training Centre (Rajput) at